Nomination of Employees to Central (Surplus Staff) Cell

404. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central (Surplus Staff) Cell of the Department of Personnel nominated certain surplus employees who joined the Cell on 31st May, 1972 (A.N.) to offices where there were actually no vacancies; if so the number of such employees category-wise;

(b) whether such working of the Central (Surplus Staff) Cell has adversely affected the services career of senior employees as these employees would have been nominated to the offices where their juniors have been nominated; and

(c) If so, the remedial action being taken by the cell?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) The surplus employees in question were all nominated against vacancies reported to the Cell. Subsequently, however, one vacancy of Stenographer was withdrawn, another vacancy of stenographer was reported to be reserved for a Scheduled Caste candidate and four vacancies of UDC were found to be available outside Delhi

(b) When two or more surplus persons on an office are selected on different dates for absorption in a grade in another office, their *inter se* seniority as it existed in the office in which they worked before being rendered surplus is maintained in the grade in which they are absorbed in the new organisation, in terms of Ministry of Home Affairs O.M. No. 9|22|68-Estt(D) dated 6th February, 1969, copy placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3677/72.]

(c) Does not arise.

Re-deployment of Surplus Staff

406. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the scheme for re-deployment of surplus staff from various offices of the Government of India provides for 'HON'BLE CONDITIONS' and 'SATISFACTORY PLACEMENT';

(b) whether the scheme also provides for the training the surplus employees in new skills, thus improving their chances for 'SATISFACTORY PLACEMENT';

(c) if so, were the surplus employees who joined the Central (Surplus Staff) Cell on 31st May, 1972 (A.N.) and thereafter provided with 'HON'BLE CONDITIONS' and 'SATISFACTORY PLACEMENT; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MNISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) to (c). Yes, Sir.

(d) Does not arise.

कांग्रेस दल के जलूस में होम गार्डस के जवानों द्वारा भाग लिया जाना

406. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अगस्त, 1972 के अंग्रेजी दैनिक 'दि मदर लैण्ड" में प्रकाशित भूतपूर्व संसद् सदस्य श्री कंवर लाल गुप्त के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि 14 अगस्त, 1972 को कांग्रेस दल द्वारा एक जलस में होम गार्डस के जवानों ने भी भाग लिया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में होम गार्डस निदेशक को गृह मंत्रालय से कोई निदेश प्राप्त हुए थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) क्योंकि 14 अगस्त, 1972 को निकाला गया मशाल जलूस भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के राष्ट्रीय समारोह का एक भाग था । अतः सरकार को होम गार्डस के स्वयं सेवकों द्वारा इसमें भाग लेने पर कोई आपत्ति नहीं थी ।

Draft Fifth Plan for Delhi

407. SHRI D. K. PANDA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Delhi Administration has approached the Union Government with a draft Fifth Five Year Plan for Delhi with an outlay of Rs. 500 crores;

(b) if so, the broad features of the proposed plan; and

(c) the Central Government's decision thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) No, Sir. However, in a document published by the Delhi Administration entitled "Union Territory of Delhi—Approach to the Fifth Five Year Plan", has estimated the requirement for the Fifth Plan in the range of Rs. 450 Rs. 500 crores, details of which have not been furnished.

(b) and (c). Do not arise.

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जिला स्तरीय विकास मंडलों की स्थापना

408. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास मंडल ने योजना आयोग से देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्रीय स्तर के मंडलों के समान ही राज्य तथा जिला स्तर पर भी विकास मंडल स्थापित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में हत्याओं के मामले

409. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1972 से सितम्बर 1972 तक हत्याओं के कितने मामले हुये;

(ख) कितने मामले पुलिस में दर्ज किये गये; और

(ग) छुरेबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जनवरी से सितम्बर, 1972 तक की अवधि के दौरान की गई हत्याओं के बारे में आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं ;

(ख) जनवरी से मार्च, 1972 तक की अवधि में पुलिस में दर्ज कराये गये हत्या के मामलों की संख्या 3572 है ।

(ग) पुलिस एक राज्य विषय होने के कारण ऐसे अपराधों की घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जाती है ।